

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा)

देहरादून दिनांक 24 जनवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में नई सुविधाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-786/XXIV(7)/2017-20(2)/15, दिनांक 10.03.2017 एवं संयुक्त परियोजना निदेशक, रूसा के पत्र संख्या 564(70)/रूसा/2017-18, दिनांक 18.12.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में नई सुविधाओं हेतु गठित डी0पी0आर0 रू0 547.50 लाख के सापेक्ष अवशेष रू0 497.77 लाख की धनराशि के विरुद्ध रू0 3,93,75,000/- (रू0 तीन करोड़ तिरानब्बे लाख पचत्तर हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वहन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा की प्रस्तावित कार्य यू0जी0सी0/रूसा के मानकानुसार हो तथा कार्य की अनुमोदित लागत रूसा के अन्तर्गत अनुमन्य लागत की सीमान्तर्गत हो अन्यथा की स्थिति में अगली किस्त स्वीकृत करने से पूर्व तदनुसार यथा आवश्यक कार्य में कटौती करते हुए यथा आवश्यक अनुमोदनोपरान्त कार्य की लागत अनुमन्य लागत के सीमान्तर्गत समायोजित किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं रूसा के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाइन तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को अवमुक्त की जायेगी तथा उनके द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

5- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

- 6- तकनीकी उपकरणों/कम्प्यूटर इत्यादि क्रय करने से पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित मानकों एवं दरों तथा विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 7- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि व्यय करते समय अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 8- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
- 9- विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
- 10- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
- 11- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- 12- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन सुनिश्चित किया जाय।
- 13- स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/xxvii(1)/2011, दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयबद्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 14- तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्ज (Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।
- 15- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य के निष्पादन हेतु एक समय सारिणी निर्धारित की जायेगी तथा कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। विलम्ब अथवा अन्य किन्हीं भी कारणों से आगणन का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
- 16- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-11 के राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103-राजकीय कॉलेज तथा संस्थान-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

17- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में निर्गत निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : 1084 (1)/XXIV(7)/2018-20(2)/15 तददिनांकित
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3-जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- 4-निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 6-कुल सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
- 7-निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड।
- 8-अपर परियोजना निदेशक, रुसा परियोजना निदेशालय, देहरादून।
- 9-बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
- 10-वित्त अनु०-3/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी०डी० बेलवाल)
उप सचिव।

